Title: Regarding need not to disinvest the profit making Public Sector Undertakings Including Hindustan Zinc Limited in Rajasthan - Laid.

श्री भेरूलाल मीणा (सलूम्बर) : महोद्य, भारत सरकार द्वारा सरकारी उप्क्रमों को निजी हाथों में देने से लाभ अर्जित करने वाले उप्क्रमों के कर्मचारियों के सामने भ्यंकर सम्स्या ख्ड़ी हो गई है। यदि कोई उप्क्रम लाभ में नहीं हैं, रुग्ण हैं, बीमार है तथा कोई कम्पनी उसे लेना चाहती है तो वह कुछ हद तक सही है। किन्तु जो उप्क्रम लगातार लाभ अर्जित कर रहे हैं, उनको निजी कम्पनियों को नहीं सौंपना चाहिए। परन्तु, केन्द्र सरकार देश के 20 सार्वजनिक क्षेत्र के उप्क्रमों की अधिसंख्य हिस्सेदारी 31 मार्च, 2001 तक बेचकर 10,000 करोड़ रुपए का विनिवेश करने का निर्ण्य न्याय्संगत नहीं है। हिन्दुस्तान जिंक लि0 राज्स्थान में मात्र एक लाभ अर्जित करने वाली ऋण-रहित बहु-इकाई सरकारी उप्क्रम है, जो कि आदिवासी क्षेत्र में है तथा इसकी उक्त इकाइयों में कार्यरत ज्यादातर श्रमिक आदिवासी हैं। यदि हिन्दुस्तान जिंक लि0 का निजीकरण कर दिया जाता है तो आदिवासियों को रोजगार एवं आरक्षण का लाभ नहीं मिल पाएगा। कम्पनी का पिछले तीन वर्षों का सकल लाभ क्रम्श: 201, 251 एवं 182 करोड़ रुपए रहा है।

मेरा भारत सरकार से अनुरोध है कि लाभ अर्जित करने वाले उप्क्रमों के साथ-साथ हिन्दुस्तान जिंक लि0 का विनिवेशीकरण नहीं किया जाए। सरकार का यह कदम देश तथा सार्वजनिक क्षेत्र के हित में होगा।